

अख़ब भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज

रविवार 26 जून 2022

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

2002 के गुजरात दंगों पर अभित शाह का इंडरव्यू: आरोप लगाने वाले पीएम मोदी से माफी मांगें

मोदी भगवान शंकर की तरह विषपान करते रहे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में जाफिया जाफरी की एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दी गई अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी थी। फैसले के बाद गृहमंत्री अमित शाह से बात की, जिसे शनिवार को रिलीज किया गया। इसमें शाह ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने सिद्ध कर दिया कि तब के गुजरात सरकार पर लगाए सभी आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, उन्हें भाजपा और मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। करीब 40 मिनट के इंडरव्यू में शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा न्यायपालिका में विश्वास रखा है।



सवाल: कोर्ट ने मोदी जी और सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है, तो आपको कैसा लग रहा है? आप तब एमएलए थे?

जवाब: सबसे पहले क्लीन चिट की बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। और आरोप क्यों गढ़े गए इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है कि ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। 18-19 साल की लड़ाई में देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बिना सभी दुश्मनों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर, सहनकर लड़ता रहा। मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है। मजबूत मन का आदमी ही ऐसा स्टैंड ले सकता है।

सवाल: पॉलिटिकल व्यू की वजह से गुजरात दंगों के दौरान पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई?

जवाब: भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आर्डिनेंसी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ

'60 लोगों को जिंदा जला दिया था, उसका समाज में आक्रोश था'

शाह ने इंडरव्यू में कहा कि एसआईटी और जांच अफसर की नियुक्ति देश की सर्वोच्च अदालत ने एनजीओ को सुनने के बाद की थी। इन अफसरों को केंद्र सरकार की ओर से भेजा गया था। उस समय तक केंद्र में यूपीओ सरकार आ चुकी थी। इकोसिस्टम बना था, उसने एक झूठ को इतना हौवा बनाकर जनता के सामने पेश किया कि सब झूठ को ही सच मानने लगे थे।

सवाल: अगर सरकार सही थी तो एसआईटी की क्या जरूरत थी?

जवाब: एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग की थी। हमारी सरकार ने कहा कि



एनजीओ ने मिलकर इन आरोपों को इतना प्रचारित किया। इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सच मानने लगे।

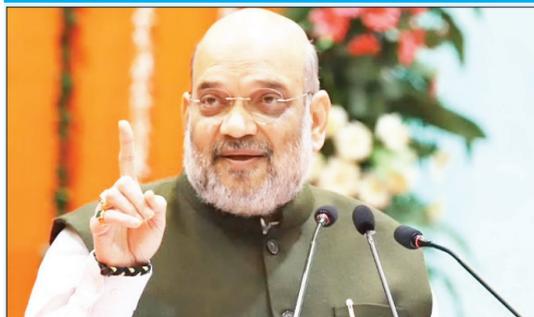
सवाल: इस वक्त तो आपको सरकार दिल्ली और गुजरात दोनों जगह थी, तो फिर इन लोगों का नेटवर्क इतना मजबूत कैसे था?

जवाब: हमारी सरकार का कभी भी मोड़िया के काम में दखल देने का ऐंटीयूड ही नहीं है। उस वक्त जो नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है। मजबूत मन का आदमी ही ऐसा स्टैंड ले सकता है।

सवाल: पॉलिटिकल व्यू की वजह से गुजरात दंगों के दौरान पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई?

जवाब: भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आर्डिनेंसी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ

'स्टिंग ऑपरेशन भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था'



अमित शाह ने सेना के बुलाने पर कहा कि जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ, उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं हुई थी। इस बात को कोर्ट ने भी माना और एंशिप्ट किया है। लेकिन दिल्ली में सेना का मुख्यालय है। जब इतने सारे सिख भाइयों को मार दिया गया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। इतने सालों तक सिख नरसंहार में विपक्ष की सरकारों के दौरान कभी गिरफ्तारियां नहीं हुईं। ये लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं? यह बात केवल मैं और मोदी जी नहीं कहते, अब सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि गुजरात पर एक दंगाई

राज्य का टैग लगाने का झूठा प्रयास किया गया। आप लोकतंत्र में संविधान और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट सच्चे हैं या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यह देश की जनता को तय करना होगा। अब आरोप लगाने वालों से पत्रकारों को पूछना चाहिए कि ये आरोप किस आधार पर लगाए गए थे। अगर आधार था तो वे लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। मैंने बहुत जल्दबाजी में जजमेंट को पढ़ा है, लेकिन इसमें तीस्ता सीतलवाड़ का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ने हर थाने में भाजपा के कार्यकर्ता को शामिल करने वाली ऐंलिक्शन दी थी। मोडिया का दबाव इतना था कि ऐसी ऐंलिक्शन को सच मान लिया गया। जनता ने कभी इन आरोपों को स्वीकारा नहीं।

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच खिंची हैं तलवारें

मुंबई: महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के पांचवें दिन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे के बेटे व कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर तोड़फोड़ की है। ठाणे के उदासनगर इलाके के दफ्तर में शिवसैनिकों ने पत्थर फेंके हैं। इसके अलावा शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के पुणे स्थित घर और दफ्तर पर भी तोड़फोड़ की गई है। डीपी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को नोटिस जारी कर 27 जून तक जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि कबों न आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए? दरअसल, शिवसेना ने 16 बागी विधायकों के सदस्यता रद्द करने की अर्जी शुक्रवार को डिप्टी स्पीकर को दी थी।

सुलगते बम पर बैठे हैं बागी विधायक : उद्धव: शिवसेना की हाईलेवल मीटिंग में



उद्धव ने शिंदे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा- शिंदे पहले नाथ थे, लेकिन अब दास हो गए हैं। उद्धव ने आगे कहा कि सुलगते बम पर बागी बैठे हुए हैं। बालासाहब का नाम लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा- वोट मांगना हो तो अपने बाप के नाम से मांगो, शिवसेना के बाप के नाम का इस्तेमाल मत करो। शिंदे ने जारी की 38 विधायकों की सूची:

गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में विधायकों की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने 38 विधायकों की सूची जारी की है। इससे पहले, शिंदे ने 23 जून को 34 शिवसेना विधायकों की सूची जारी की थी। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए शिंदे को सिर्फ 37 शिवसेना के विधायकों की जरूरत है। वहीं राज्य में लगातार हो रही हिंसा के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा है कि विधायकों की सुरक्षा हटा दी गई है, अगर उनके परिवार को कुछ हुआ, तो उसके लिए उद्धव और आदित्य जिम्मंदार होंगे। शिंदे के करीबी दीपक केसकर ने बताया कि गुवाहाटी में बागी विधायकों ने शिवसेना बालासाहब ठाकरे नाम से नए गुट बनाने की घोषणा की है। पुणे में हिंसा को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है।

पाक में 26/11 मुंबई हमले से जुड़े आतंकी को 15 साल की सजा

लाहौर। पाकिस्तान की एक आतंकीरोधी अदालत ने 26 नवंबर, 2008 के मुंबई हमले के हैंडलर और आतंकी साजिद मजीद मीर को आतंकी फंडिंग के मामले में 15 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई है। लश्कर और जमात-उद-दावा से जुड़े आतंकी फंडिंग के केस देखने वाले एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इस वकील के मुताबिक इस साल अप्रैल में गिरफ्तार किए जाने के बाद से मीर कोट लखपत जेल में बंद है।

राष्ट्रपति चुनाव: भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करेंगी मायावती



पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्हीने कहा कि हमारा यह फैसला न तो भाजपा या एनडीए के समर्थन में है और न ही विपक्ष के खिलाफ। हम अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज की योग्य और कमठ महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में हैं। मायावती ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चयन करने के लिए 15 जून को बुलाई थी और केवल चयनित पार्टियों को आमंत्रित किया इसके साथ ही जब शरद पवार ने 21 जून को एक बैठक बुलाई, तो बसपा को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। यह उनके जातिवाद के उद्देश्यों को दशाती है

मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्हीने कहा कि हमारा यह फैसला न तो भाजपा या एनडीए के समर्थन में है और न ही विपक्ष के खिलाफ। हम अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज की योग्य और कमठ महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में हैं। मायावती ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चयन करने के लिए 15 जून को बुलाई थी और केवल चयनित पार्टियों को आमंत्रित किया इसके साथ ही जब शरद पवार ने 21 जून को एक बैठक बुलाई, तो बसपा को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। यह उनके जातिवाद के उद्देश्यों को दशाती है

रिजर्व बैंक ने आईओबी पर 57.5 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) पर 57.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना आईओबी के समय पर घोखाधड़ी की जानकारी नहीं देने पर लगाया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक आईओबी पर यह कार्रवाई कुछ मानदंडों तथा घोखाधड़ी से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने के मामले में हुई है। आरबीआई ने कहा कि मार्च 2020 के अंत में अपनी वित्तीय रिपोर्टों में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और रिपोर्टों की जांच के

आधार पर यह जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि आईओबी पता लगाने की तारीख से तीन हफ्ते के भीतर एटीएम कार्ड क्लॉनिंग या स्किमिंग से जुड़े घोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी देने में विफल रहा था। दरअसल यह जुर्माना कमरिश्चियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की घोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई की ओर से जारी निर्देशों से जुड़ा था। बैंक नियामक ने कहा कि इस कार्रवाई का आईओबी ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या करार को वैधता से कोई संबंध नहीं है।

कोरोना: देश में 15,940 नए संक्रमित मिले

नई दिल्ली: देश में बीते 24 घंटे में 15,940 नए कोरोना संक्रमित मिले और 20 लोगों की महामारी से मौत हो गई। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 91 हजार के पार पहुंच गई है। हालांकि, तुलना में नए संक्रमितों की संख्या कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी बीते 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार देश में औसत दैनिक कोरोना संक्रमण दर 4.39 फीसदी है। हालांकि कई राज्यों में यह 5 से 10 फीसदी के बीच है। देश में सक्रिय केस में बीते 24 घंटे में 3495 की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 91,779 हो गए। वहीं, 20 और मौतों के साथ



कुल मृतक संख्या 5,24,974 हो गई है। 12 राज्यों में बढ़ी कोरोना की रफ्तार: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 10 जून के बाद 12 राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। इसमें महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, पंजाब में साप्ताहिक मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है।

वैक्सिन ने देश में 42 लाख से अधिक मौतें रोकें: देश में कोरोना से हुई मौतों को लेकर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने बड़ा दावा किया है। साल 2021 में कोविड वैक्सिन देश में 42 लाख से अधिक मौतें रोकने में सफल रही है। यह स्टडी 8 दिसंबर, 2020 से 2021 तक देश में मृत्यु दर के अनुमानों पर आधारित है। डब्ल्यूएचओ ने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच देश में 47 लाख मौतों का अनुमान जताया था। अगर राज्य में कोरोना की स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,205 नए केस सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई।

अब सिर्फ पौष्टिक खाना मिलेगा; चिप्स-समोसा, कोल्ड ड्रिंक समेत फ्राइड और जंक फूड बैन

बोर्ड का फैसला: अमरनाथ यात्रा के लंगरों में सेहत का ख्याल

जम्मू-कश्मीर: 2 साल बाद शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगरों में फ्राइड फूड, जंक फूड, स्वीट डिश, चिप्स, समोसे जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। ऐसी दर्जनों चीजें बैन कर दी गई हैं। फ्राइन बोर्ड ने सभी लंगर कमिटियों को पत्र लिखा है कि यात्रियों को हरी सब्जियां, सलाद, मक्के की रोटी, सादी दाल, लो फेट दूध और दही जैसी पौष्टिक चीजें ही दी जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय पर किए गए इस फैसले में बताया गया है कि हेल्दी फूड यात्रियों की सेहत ठीक

रहेगा। उनका एनर्जी लेवल ठीक होगा। इस बीच, श्री अमरनाथ गुफा के रास्ते में लगातार मौसम बदल रहा है, जिससे यात्रा में परेशानी नहीं होगी।

रहा है, दो दिन से बर्फबारी जारी है। ऐसे में यात्रा शुरू करने में देरी भी हो सकती है। फ्राइन बोर्ड ने 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई है। 2019 में कुल 3.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इन पर पाबंदी: मांसाहार, शराब, तंबाकू और गुटखा पर पाबंदी रहती ही है, लेकिन इस बार पुलाव, फ्राइड राइस, पूरी, भूटूरा, पिज्जा, बर्गर, तले परांठे, डोसा, तली हुई रोटी, ब्रेड बटर, अचार, चटनी, पापड़, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, इन्फेक्शन से कोरोना संक्रमण की

नमकीन, मिक्सचर, पकोड़ा, समोसा और हर तरह की डीप फ्राइड चीजें नहीं मिलेंगी। 120 संस्थाएं लगाएंगी लंगर: देशभर से 120 समाजसेवी संस्थाएं यात्रा मार्ग पर लंगर लगाएंगी। ये लंगर बालटाल कैम्प, बालटाल-डोमेल के बीच, डोमेल, रेलपट्टी, बरारीमार्ग, सांगम, नुनवान, चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी-पिस्सुटाप के बीच, पिस्सुटाप, जोजीबल, नागाकोटी, शेषनगर, वावबल, पोषपट्टी, केलनार, पंचचरण व पित्रि गुफा के पास लगेगी।

वाचनाड: मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की वाचनाड इकाई के कार्यकर्ता हैं। स्थानीय कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह की रिमांड पर सौंपा है। मामले की जांच मन्तवाडी के पुलिस उपधीक्षक कर रहे हैं। एडीजीपी के नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम जल्द ही जांच हाथ में लेगी। एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी के वाचनाड दफ्तर में तोड़फोड़ करने के कुछ घंटों बाद

केरल की वाम सरकार ने शुक्रवार रात को एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी से उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया था और कलपेट्टा के डीएएसपी को निलंबित कर दिया था। इस बीच, विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ और हिंसा की कार्रवाई सत्तारूढ़ मार्क्सवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर की गई।

